जनपद प्रतापगढ़ के व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास में बडौदा ग्रामीण बैंक का योगदान

सत्यम सिंह*

औद्योगिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें उद्योगों का नियमित एवं क्रमिक विकास होता रहता है तथा धीरे–धीरे इनमें नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश होता रहता है। संकुचित दृष्टिकोंण से औद्योगीकरण से तात्पर्य विनिर्माण एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना एवं विकास करना है जब कि विस्तृत दृष्टिकोंण के अन्तर्गत औद्योगीकरण में मात्र विनिर्माणी एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना एवं विकास ही नहीं किया जाता बल्कि अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समन्वित एवं विस्तृत विकास कर उनमें परिवर्तन लाया जाता है। यूजीन स्टेले के अनुसार ''औद्योगिक विकास से तात्पर्य कारखानों, मिलों, खानों, शक्ति संयंत्रों एवं रेलों आदि से सम्बन्धित विकास की क्रियाओं से है, मुख्यतया उन क्रियाओं के विकास से है जिनसे वाह्य आधुनिक संरचना का निर्माण तथा संचालन होता है।''

जब किसी देश में औद्योगिक विकास होने लगता है तब उत्पादन की परम्परागत विधियों के स्थान पर क्रमशः अपेक्षाकृत नवीन विधियों एवं मशीनों का प्रयोग होने लगता है। उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं में समयानुसार एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। सामान्यतया औद्योगिक विकास सतत् एवं गतिशील होता है। जिस देश में औद्योगीकरण की गति जितनी अधिक होती है, वह देश उतनी ही तेजी से आर्थिक विकास करता है।

भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकता एवं महत्व

भारत जैसे विकासशील देशों के तीव्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण परम आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के अभाव में देश का समुचित विकास होना अधूरा ही रहेगा। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाएं औद्योगीकरण के माध्यम से ही आज आर्थिक विकास के उन्नत शिखर पर पहुंच सकी है। सामान्यतया कृषि की अपेक्षा उद्योगों में प्रति व्यक्ति आय एवं उत्पादन अधिक होता है। आतरिक एवं वाह्य बचतें आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं जिसके फलस्वरूप अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। आज वही देश विकसित माना जाता है जो औद्योगिक दृष्टि से आगे होता है भारत जैसे विकासशील देश को यदि विकसित देशों की दौड़ में शामिल होना है तो उसे तीव्र सन्तुलित एवं उत्तरोत्तर औद्योगीकरण का सहारा लेना होता।

उ0प्र0 बड़ौदा ग्रामीण बैंक द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में योगदान निवेश ऋण

कृषि पर आधारित क्रियाकलापों मे आय एवं रोजगार में वृद्धि की एक सीमा है जिससे ज्यादा होना सम्भव नहीं है। अतः गैर कृषि क्षेत्र जहां पर आय एवं रोजगार में वृद्वि की अधिक सम्भावना है, की तरफ ध्यान देना जरूरी हो गया है। नये उद्योग को चालू करने हेतु टर्म लोन एवं क्रियाशील पूंजी व पुराने उदद्योगों के लिए क्रियाशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जनपद मं कुल 9 कार्यरत कारखाने हैं जब कि पंजीकरण 18 का है। ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की संख्या निम्नवत् है– खादी ग्रामोद्योग 2532, खादी ग्रामोद्योग द्वारा परिवर्तित ग्रामोद्योग 23, इंजीनियरिंग 450, रासायनिक 483, विषायन 623, हथकरघा 1430, हस्तशिल्प 149 एवं अन्य 1922 हैं। इनके द्वारा दाल, चावल, लकड़ी के सामान, चिराई, प्रिन्टिंग प्रेस, चमड़े के जूते, ईट लकड़ी एवं लोहे के फर्नीचर, आलमारी एल्यूमिनियम के बक्से, साबुन, अगरबत्ती, कापियां, रेडीमेट कपड़े, प्लास्टिक, पालीथिन बैग, मोमबत्ती आदि अनेक प्रकार के सामानों का निर्माण किया जाता है। लधु औद्योगिक इकाइयों के कारण ग्रामीण अंचलों में यह गतिविधियां प्रारम्भ हो चुकी हैं। जनपद में बड़ी औद्योगिक इकाई एटीएल बन्द पड़ी है। आंवले को प्रोसेस करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं तथा इसमें ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है।

आधारभूत सुविधाएं, कमियां एवं सहायक सेवाएं

जनपद में कच्चे माल पर आधारित उद्योग जैसे तेलघानी, एक्सप्रेलर, बेकरी, आंवला, मुरब्बा, चटनी अचार आदि हैं। मांग पर आधारित उद्योग जैसे कपड़े, लकड़ी के सामान, कागज, चमड़ा, रबड़, प्लास्टिक आदि भी काफी मात्रा में हैं। दक्षता पर आधारित जैसे टी.वी. रेडियो वी सी आर, साइकिल, ट्रैक्टर, पम्पसेट आदि की मरम्मत हेतु दुकान भी है।

* **शोध छात्र, वाणिज्य संकाय, मदनमोहन मालवीय पी0जी0 कालेज कालाकाँकर, प्रतापगढ़**

आधारभूत सुविधाओं में कमियां जैसे उद्यमियों को विद्युत प्रदूषण बोर्ड एवं संबंधित विभागों से स्वीकृत मिलने में विलम्ब एवं पारदर्शिता का अभाव है। जनपद मुख्यालय से लगा हुआ सुखपाल नगर क्षेत्र यूपीडेस्को द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्षेत्र में उद्योगों का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में केवल 9 फैक्ट्री ही स्थापित हैं। क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं जैसे अच्छी सड़कें बिजली की कमी की वजह से उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है। गैर कृषि क्षेत्र में वर्ष 2013–14 की सम्भाव्यता ऋण योजना निम्न प्रकार आकलित की गयी है–

तालिका सं0 1

(रू0 लाख मे)

क्रिया–कलाप	2013–14 का लक्ष्य					सम्भाव्यता 2014–15			
	इकाई	इकाई लागत	भौतिक	वित्तीय	बैंक ऋण	इकाई लागत	भौतिक	वित्तीय	बैंक ऋण
लघु उद्योग	संख्या		100	100.00	90.50	1	168	168.00	15120
हथकरघा	संख्या	03	75	22.50	20.25	03	101	30.30	27.27
अति लघु उद्योग	संख्या	0.3	125	37.50	33.75	0.3	170	51.00	45090
गृह कुटीर उद्योग	संख्या	0.3	150	45.0	4.50	0.3	235	70.50	63.45
फल प्रसंस्करण	संख्या	3	130	390.00	351.54	3	132	390.00	356.40
योग			580	595.00	536.54		806	709.80	614.22

तालिका सं0 2

उद्देश्यवार–विकासखण्डवार सम्भाव्यतायुक्त भौतिक एवं वित्तीय आकलन 2011–12

क्रिया कलाप	झाकई लागत (रू0 लाख में)	इकाई साइज		आसपुर देवसरा	बाबागंज	बिहार	बाबा बेलखर नाथ	गौरा	कालाकांकर	कुण्डा
अति लघु उद्योग	0.3	सं0	बैंक ऋण	1.35	1.62	1.35	1.35	1.62	1.35	1.35
			भौतिक	8	8	8	8	8	8	9
गृह कुटीर उद्योग	0.3	सं0	बैंक ऋण	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.43
			भौतिक	15	15	15	15	15	15	15
फल प्रसंस्करण	3		बैंक ऋण	4.05	4.05	4.05	1.05	4.05	4.05	4.05
			भौतिक	7	7	8	8	8	8	12
				18.9	18.9	21.6	21.6	21.6	21.6	32.4
योग			बैंक ऋण	35.46	35.73	38.16	38.16	38.43	38.16	49.23

लालगंज	लक्ष्मणपुर	मान्धाता	मंगरौरा	पट्टी	सदर	रामपुर संग्रामगढ़	संडवा चन्द्रिका	सांगीपुर	शिवगढ़	योग
1.35	1.35	1.35	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	27.27
9	8	12	12	12	12	12	12	12	12	170
2.43	2	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	45.9
15	15	15	15	15	10	10	10	10	15	235
4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	2.70	2.70	2.70	2.70	4.05	63.45
9	7	7	7	7	10	7	7	7	6	132
24.3	18.9	18.9	18.9	18.9	27	18.9	18.9	18.9	16.2	356.40
41.13	35.46	36.54	37.08	36.18	43.83	35.73	34.83	35.73	34.38	644.22

नाबार्ड बुलिटेन 2013 जनपद प्रतापगढ़

जनपद प्रतापगढ़ के विकास हेतु उ0प्र0 बडौदा ग्रामीण बैंक के और प्रभावी योगदान हेतु सुझाव

1. भारत सरकार द्वारा किए गए ऋण माफी से वे किसान बहुत असन्तुष्ट हैं जो अपना ऋण समयानुसार जमा किया करते थे क्योंकि इस योजना का लाभ केवल ऐसे किसानों को मिला है जो ऋण लेकर वापस नहीं किये थे।
2. पशुपालक किसान पशुधन से सम्बन्धित आवश्यक सेवाएं न होने की वजह से जिसमें सरकारी पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों का न होना तथा दवाइयों का न होने की वजह से बेहद नाखुश हैं क्योंकि इन सेवाओं की कमी से पशुपालन एवं भेड़, बकरी एवं मुर्गीपालन करने वाले किसानों को अनावश्यक हानि उठानी पड़ती है।
3. जनपद में अनाज के भण्डारण की कमी है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार तथा बैंकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भण्डारण क्षमता बढ़ाने हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु ग्रामीण गोदाम योजना तथा कोल्ड स्टोरेज योजना के तहत भण्डारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
4. जनपद में दुग्ध पालकों की समस्या को देखते हुए दुग्ध डेयरी तथा चिलिंग प्लांट स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
5. जनपद में आंवला अधिक होता है। यहां का आंवला महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान आदि प्रदेशों में जाता है। आंवला मण्डी महुली में है परन्तु उस पर आढ़तियों का बोलबाला है। किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। दूसरे सरकार द्वारा आंवला को बन उपज माना जाता है जिससे किसानों को 12 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ता है। भारत सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है जिससे किसानों का अनावश्यक शोषण न हो।

संदर्भ सूची

1. Economic Survey – 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08.
2. Government of India: First Report of the National Income Committee April, 1951.
3. Government of India :Problems in the Third Plan & Critical Miscellany.
4. G.R. Saini : Farm Size Resource Use Efficiency and Income Distribution.
5- G.M. Meir and R.E.B. Baldwin : Economic Development Theory and Policy.
6- Haberler : The Theory of International trade.
7- Harper and Brothers : India : The Awaking giant.
8- J.M. Keynes : The end of Laissez Faire.
9- J.A. Schumpeter : The Theory of Economic Development.
10- K.M. Raj Growth : Models and Indian Planning.
11- Khusro, A.M. : Economics of Land Reform and Farm Size in India Introduction.
12- Mahbub-ul-Haq : Human Development in South Asia.

13- Myrdal g. : Asian Drama.

जरनल एवं समाचार पत्र–पत्रिकाएं

1– प्रतियोगिता दर्पण
2– कुरूक्षेत्र
3– एस0बी0आई0 बुलेटिन
4– आर0बी0आई0 बुलेटिन
5– NABARD बुलेटिन
6– इकोनामिक टाइम
7– फाइनेन्सियल एक्सप्रेस
8– हिन्दुस्तान टाइम्स
9– अमर उजाला
10– आज